'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2016-18
WPP Licence No.- U(C)-101/2017-18
R.N.I. No. 68180/98

Date of Publication : 31.07.2017
Date of Posting on concessional rate :
2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन – जस्टिस पब्लिकेशंस, टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, फोन : 23354841–42

Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com

● वर्ष : 20 ● अंक 17 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● कुल पृष्ठ संख्या 8 ● 16 से 31 जुलाई, 2017

लखनऊ में परिसंघ का सम्मेलन सम्पन्न

पदोन्नति एवं निजी क्षेत्र में आरक्षण हेतु अखिल भारतीय परिसंघ ने भरी हुंकार

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की उत्तर प्रदेश इकाई के तत्वाधान में 16 जुलाई 2017 को लखनऊ के रवीन्द्रालय सभागार में 'आरक्षण की रक्षा– सामाजिक सुरक्षा' को लेकर प्रदेश–स्तरीय चिन्तन शिविर आयोजित हुआ, जिसमें पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में परिसंघ के कार्यकर्त्ताओं ने शिरकत की, जिसको परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय डॉ. उदित राज जी ने सम्बोधित किया। इस कार्यक्रम में लगभग 2 घंटे के भाषण में दलितों और आरक्षण से सम्बंधित विषयों पर चर्चा की जिसमें विषेश रूप से प्रदेश में दलितों पर जातीय अत्याचार, प्रदोन्नति में आरक्षण बिल को पास कराने हेतु, निजी क्षेत्र में आरक्षण को लागू करवाना, उच्च न्यायपालिका में आरक्षण, ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति, अनुसूचित वर्गो के किशोरों को खेलों के लिए संसाधनों की मांग।

इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर जोर दिया। सभी से अपील किया कि हर हाल में सभी लोग फेसबुक, ट्वीटर और व्हाटसअप का इस्तेमाल अवश्य करे। सभागार में आये भारी संख्या में कर्मचारियों व अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देश दिया गया कि वे अपनी–अपनी संस्थाओं पर नजर बनाये रखे, अगर कहीं कोई आरक्षण या शोषण किसी कर्मचारी का हो रहा है तो उसे परिसंघ को अवगत करायें। परिसंघ इसकी आवाज उठाने को प्रतिबंद्ध है, क्योंकि परिसंघ एक सरकारी कर्मचारियों के सामाजिक संगठनो से बना है।

इससे पहले परिसंघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सुशील कुमार कमल ले सभी 75 जिलों से जल्द ही टीमों के गठन करने को कहा, साथ ही उत्तर प्रदेश में परिसंघ के तत्वाधान में कुछ अलग से प्रकोष्ठ बनाने और उसके जरिये वंचितों को लाभ पहुंचाने के अपने प्लान की जानकारी दी।

<u>सोसल मीडिया सेल :</u>

परिसंघ का न्यूज पोर्टल बनाना, परिसंघ का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, ट्वीटर, व्हटसएप, की टीम अलग से बनाने का निर्णय लिया गया।

<u>कानूनी सलाह सहायता सेल :–</u>

सभी जिलो में समाज के अधिकारियों की एक टीम बनाना जो निःशुल्क समाज के लोगों को कानूनी सलाह एवं केश लड़ना, सरकारी कर्मचारियों की सेवा सम्बंधी शिकायतों का निवारण कोर्ट के बाहर से कराना।

चिकित्सा सम्बधी सहायता सेल :–

कमजोर एवं निसक्त जनो को सामाजिक/ सरकारी एवं निजी डाक्टरों/ सर्जनों द्वारा मुक्त सलाह एवं इलाज कराने की व्यवस्था।

प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार कमल ने पूरे प्रदेश के लगभग 46 जिलों से आये हजारों की संख्या में कार्यकर्त्ताओं का आभार व्यक्त किया और प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद एवं बधाई दी जिनकी वजह से सम्मेलन ऐतिहासिक बना।

विशेष रूप से लखनऊ जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा जी को इतने कम समय में इतना सफल एवं रिकार्ड के साथ अयोजन करने पर विशेष आभार व्यक्त किया। साथ ही सभी पदाधिकारियों से अनुरोध किया जिससे जल्द ही दिल्ली की तर्ज पर एक महारैली का रमाबाई अम्बेडकर मैदान, लखनऊ में आयोजन किया जाएगा।

प्रदेश माहसचिव नीरज चक ने सभी कार्यकर्त्ताओं का आभार व्यक्त किया और साथ ही जमीनी स्तर पर टीम बनाकर प्रदेश के हर जिले से लेकर गांवो तक परिसंघ को पहुंचाने का आवाहन किया और साथ ही सभी को सदस्यता अभियान चलाकर परिसंघ को जोड़ने पर बल दिया और सभी से कहा हमें हर हाल में रमाबाई अम्बेडकर मैदान में एक महारैली का आयोजन करना है, जिसमें लाखों की संख्या में परिसंघ के कार्यकर्त्ता एकत्रित होकर अपनी ताक़त सरकार को दिखा दें।

बरेली से आये प्रदेश महासचिव राजकुमार जी ने हर ब्लाक, तहसील स्तर पर कैडर कैम्प करवा कर कार्यकर्ता तैयार करने पर जोर दिया और साथ ही लोगों को बाबा साहब अम्बडेकर मिशन के प्रति खासकर सरकारी कर्मचारियों को जागृत करना, जिससे इनकी भागीदारी सामाजिक अन्दोलनों में हो सके। इसके साथ ही उन्होंने रमाबाई अम्बेडकर मैदान में महारैली के प्रचार को अभी से शुरू करने को कहा।

प्रदेश कोषाध्यक्ष संजय राज ने लोगों से ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने पर जोर दिया और आर्थिक रूप से परिसंघ की उत्तर प्रदेश इकाई को मजबूत बनाने की अपील किया।

सैकड़ो कार्यकर्त्ताओं के साथ पहुंचे कानपूर मंडल अध्यक्ष जितेन्द्र सिंह ने अपने मंडल के 6 जिलों में कैडर कैंप आयोजित कर परिसंघ के मिशन को घर–घर तक पहुंचाने को कहा।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में आए प्रसिद्ध लेखक एवं बहुजन डाईवीसिटी मिशन के अध्यक्ष एच.एल. दुसाध जी एवं सोसल मीडिया एक्टिविष्ट भी उपस्थित रहे।

प्रदेश प्रचारक रामहेत अनुरागी जी भी सैकड़ो लोगो के साथ पहुंचे, प्रदेश संगठन सचिव, भानू प्रताप, प्रदेश कार्यालय सचिव अरविन्द

मंच पर बैठे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज जी के साथ प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार कमल

डीएमओ परिसंघ की स्थापना

काफी दिनों से महसूस किया जा रहा था कि पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को कैसे साथ जोड़ा जाए। यह हमारी तरफ से ही नहीं था बल्कि इन वर्गों की ओर से भी पहले से ही मांग की जा रही थी। निजीकरण और भूमण्डलीकरण की मार इन वर्गों पर भी पड़ रही है और इसलिए मिलकर ही संघर्ष करने से समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बात यहीं तक नहीं है बल्कि अनुसूचित जाति/जन जाति परिसंघ का जो स्वरूप है, वह भी कहीं न कहीं गैर कर्मचारी दलित एवं आदिवासी को संगठन से जुड़ने में हतोत्साहित करता है। परिसंघ मूलतः कर्मचारियों व अधिकारियों के द्वारा ही संचालित होता रहा है और आज भी है।

डीएमओ का मतलब – दलित, मॉइनॉरिटी और ओबीसी। जब लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं और परिस्थिति भी अनुकूल है, ऐसे में क्यों न दायरा बढ़ाकर ताक़त बढ़ायी जाए। जब हमारा फैलाव 85 प्रतिशत आबादी के बीच होगा तब दलतों में उपजातिवाद भी कम होगा। आज हमारे सामने यह भी समस्या रही है कि हम दलितों और आदिवासियों तक सीमित थे और उसमें भी जातियों के आधार पर बंटवारा होता रहा है। तो ऐसे में वह ताक़त नहीं हासिल कर पाए कि अपनी मांगों को हम मनवा सकें। जब संख्या ज्यादा हमारे साथ होगी तो उपजातिवाद भी असरदार कम रहेगा। हम अपने अनुभव के आधार पर भी ऐसा निर्णय ले रहे हैं। गत् कई वर्षो से लगातार संघर्ष तो हो रहा है लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही है। बहुजन समाज पार्टी को उतनी ताक़त कभी न मिली होती अगर शुरू में दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों व पिछड़ों को न जोड़ा होता। इन विभिन्न समुदायों के समर्थन से बड़ी ताक़त बनी और इससे दलित भी गोलबंद हुए। गत् 15 वर्षो में जो साथी इंडियन जस्टिस पार्टी या अन्य रूप से जुड़े थे, वे छूट गए थे और इसका हमें दर्द भी था, इसलिए भी इस नए मंच को तैयार करने की आवश्यकता थी, उन सभी से आग्रह है कि हमसे सम्पर्क करें और मिलकर संगठन बढ़ाएं।

– परमेन्द्र, संयोजक, मो. 9013869539, 8826180767

सम्मेलन में उपस्थित जनसमूह का दृश्य

शास्त्री, प्रदेश कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र कमल, प्रदेश मीडिया प्रभारी भरत लाल, जोनल कोर्डीनेटर आर. के कमल, जोनल कोर्डीनेटर इंजी राम लखन, जोनल कोर्डीनेटर इन्द्रेश सोनकर, फैजाबाद मंडल अध्यक्ष जियालाल, आगरा मंडल प्रभारी गिरिष दिवाकर, मंडल अध्यक्ष जितेन्द्र कमल आदि अपने सैकड़ो साथियों के साथ पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाया।

कबीर महासभा लखनऊ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत वर्मा ने भी अपने विचार रखे। दिल्ली से आये राष्ट्रीय सदगुरू कबीर कोरी/ कोली महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजी आर. के. वर्मा जी एवं बिजनौर से आये श्रीमती रीता भुईयार भी आपनी टीम के साथ उपस्थित रहीं।

अंत में राष्ट्रीय चेयरमैन डॉ. उदित राज जी ने लोगों की समस्याओं को सुना व उत्तम निवारण का भरोसा दिलाया।

कार्यक्रम के संदर्भ में एच. एल. दुसाध द्वारा लिखित उत्साहवर्धक लेख नीचे छापा जा रहा है।

– भरत लाल,
मीडिया प्रभारी
उत्तर प्रदेश,परिसंघ

***

निजी क्षेत्र में आरक्षण की बेहतर लड़ाई डॉ. उदित राज ही लड़ सकते हैं

–एच.एल.दुसाध

मित्रों, डॉ.उदित राज के विषय में तो बहुत पहले से ही मेरी धारणा रही है कि वह वर्तमान भारत की श्रेष्ठतम राजनीतिक प्रतिभाओं में से एक हैं। उसी डॉ.राज को आज जब लखनऊ के रवीन्द्रालय सभागार में अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ द्वारा 'आरक्षण की रक्षा, सामाजिक सुरक्षा' विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में सुनने का अवसर मिला, लगा मेरी धारणा भ्रांत नहीं थी। इससे पहले उन्हें 2014 के अक्तूबर में 'बहुजन डाइवर्सिटी मिशन' द्वारा आयोजित आठवें 'डाइवर्सिटी डे' प्रोग्राम में सुना था। उसमें उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में दलित बुद्धिजीवियों के प्रति हिकारत भरी टिपण्णी करके हमें भारी निराश किया था। बहरहाल कल जब फेसबुक पर डॉ.लालजी निर्मल के एक पोस्ट के जरिये जब यह विदित हुआ कि वह 16 जुलाई को रवीन्द्रालय में आरक्षण बचाने पर केन्द्रित एक रैली को संबोधित करने वाले हैं, सामान्यतया सभा–सेमिनारों से परहेज करने वाला आपका मित्र दुसाध बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में उन्हें सुनने का मन बनाये बिना न रह सका । अतः आज साढ़े 12 बजे तक रवीन्द्रालय पहुँच गया और डॉ.उदित राज का पूरा भाषण सुना।

उदित राज में आया है सकारात्मक बदलाव

तीन साल पहले जिस उदित राज को सुना था, उसमें खासा सकारात्मक परिवर्तन पाया। तब उनके चेहरे पर सुकून का भाव ढूँढना मुस्किल था। वह बेहद चिडचिडे थे। किन्तु इस बीच उनके व्यक्तित्व में सुखद बदलाव पाया। चेहरे पर भारी शांति और सोच में सकारात्मक बदलाव, विपक्षियों के प्रति पहले जैसी उग्रता की जगह ,खासा सम्मान का भाव। बहरहाल पिन ड्राप साइलेंट के बीच आज उन्होंने जो सवा घंटे का जो स्पीच दिया, उसे सुनकर ऐसा लगा जैसे बंदे ने अपना कलेजा निकालकर रख दिया है। उन्होंने जिन तर्कों के साथ बेहद आहत भाव से यह कहा कि मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, तो श्रोताओं के चेहरे पर अविश्वास का भाव नहीं उभरा। लोगों को लगा कि उन्होंने बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ने और आरक्षण बचाने के लिए जो त्याग किया है, उसका योग्य प्रतिदान देने में हम चूक गए हैं। उनका स्पीच स्तब्धकारी था। सुनने के बाद तमाम लोग दलित समाज के भविष्य को लेकर बेचौन हो उठे।

सामजिक बदलाव की लड़ाई मोबाइल फोन से लड़ी जाएगी

बहरहाल आज डॉ उदित राज जी ने जो कई नई बातें कहीं उनमे से एक खास बात यह थी कि सामाजिक बदलाव की लड़ाई मोबाइल के जरिये लड़ी जाएगी अतः आप हर हाल में इंटरनेट से जुड़े और दूसरे जरुरी खर्चे छोड़कर कमसे कम 6–7 हजार का अच्छा मोबाइल अपने पास अवश्य रखें। उन्होंने इसकी अहमियत का अहसास करते हुए कहा कि जितना ज्ञान मैं स्कूल और यूनिवर्सिटी में पढ़कर नहीं हासिल कर पाया,उससे कही ज्यादा फेसबुक और गूगल से पाया। उन्होंने यह भी कहा कि जैसे आज अपना समाज बीजेपी से भड़कता है , उसी तरह आजादी के समय कांग्रेस लोग विदकते थे किन्तु, उसी कांगेस से जुड़कर बाबासाहेब मंत्री बने और मंत्री – पावर का इस्तेमाल समाज के लिए किया। 12 वर्ष तरह तरह से प्रयास करने के बाद अंततः मैं बीजेपी के सौजन्य से संसद में पहुंचा और आप पाएंगे कि विगत तीन सालों में जितना सवाल एससी/एसटी के लिए मैंने उठाया संभवतः आपके समाज के चार दर्जन अन्य संसद भी मिलकर उतना सवाल नहीं उठाये। डॉ.राज के इस दावे में दम था, इसका साक्ष्य उक्त अवसर पर वितरित की गयी 8 पृष्ठीय पुस्तिका– डॉ.उदित राज द्वारा संसद में उठाये गए प्रमुख मुद्दे–में मिलता है।

लाखों की तादाद में सड़कों पर उतरे बिना नहीं मिल सकता निजी क्षेत्र में आरक्षण

लेकिन आज की सभा में डॉ.राज ने जो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात कही वह यह थी कि लाखों की तादाद में जगह–जगह सड़कों पर उतरे बिना नहीं मिल सकता निजी क्षेत्र में आरक्षण। इसके लिए उन्होंने राजस्थान के जाटों और गुजरात के पटेलों का उदहारण देते हुए कहा कि मैंने भारी कोशिशों के बाद निजीक्षेत्र में आरक्षण का बिल पेश करवा दिया है, लेकिन यह पास होगा तभी जब आप लाखों की संख्या में संगठित होकर राजस्थान के जाटों और गुजरात के पटेलों की भांति सडकों पर उतरेंगे।

राजनीतिक नहीं, सामाजिक शक्ति पर निर्भर होकर लेना होगा आरक्षण

डॉ. राज ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आजाद भारत में आपके आधे अधिकार खत्म किये जा चुके हैं। आपके समाज में भारी संख्या में लोग पढ़–लिखकर तैयार हो रहे हैं, पर नौकरियां नहीं। जो बची हुई है वह आउट सोर्सिंग, एफडीआई इत्यादि के जरिये खत्म हो रही हैं। आप न अखबार के मालिक हैं न चैनलों के, दुकान–व्यापार में कोई हिस्सेदारी नहीं,इसलिए हर हाल में आरक्षण बचाना होगा। लेकिन यह राजसत्ता के जोर से बचने को रहा। क्योंकि दलित समाज जिस तरह जाति/उपजातियों में बात दिया गया है,उससे आने वाले कई वर्षो तक दलितों के लिए राजसत्ता पर कब्जा जमाना सपना बना रहेगा। ऐसे में आरक्षण बचाने के लिए राजनीतिक शक्ति के बजाय सामाजिक शक्ति पर निर्भर रहना होगा। जिस तरह राजस्थान के जाटों और गुजरात के पटेलों ने राजनेताओं को दरकिनार कर उन्होंने सामजिक शक्ति की ताकत से आरक्षण की अपनी मांगे मनवाया वही काम आपको भी करना होगा। आप अगर राजसत्ता के जोर से निजीक्षेत्र और दूसरे क्षेत्रों में आरक्षण पाने का सपना देख रहे हैं, तो यह सपना भूल जाइए। सिर्फ और सामाजिक शक्ति के जोर से बात बन सकती है। खुद सत्ताधारी पार्टी का सदस्य होकर भी जिन जोरदार डॉ. राज सामाजिक शक्ति पर निर्भर रहने का आह्वान किया वह विस्मयकर घटना ही कही जाएगी। उनके इस नए आह्वान ने उपस्थित लोगों को जिस गहराई से स्पर्श किया, उससे लगा परिसंघ आरक्षण बचाने की लड़ाई को एक नया आयाम देने में सफल होगा।

बहरहाल आज का आयोजन काफी सफल रहा। जब मैं12 बजे के करीब हॉल में प्रवेश किया, उस समय लोगों को शोचनीय उपस्थिति देखकर लगा यह फ्लॉप साबित होगा। किन्तु डॉ.राज के मच पर पहुचने के बाद विभिन्न इलाकों के कार्यकर्त्ता सौ–सौ दो–दो सौ के समूह में पहुँचने लगे। देखते ही देखते हॉल भर गया। सिर्फ सप्ताह भर की तैयारी में इतनी भारी संख्या लोगों की उपस्थिति से आयोजक काफी उत्साहित थे। इसी उत्साह में उन्होंने निकट भविष्य में रमाबाई आंबेडकर पार्क भरने की घोषणा कर दिया। लोगों के उत्साह का आलम यह था कि जब डॉ. राज ने नैनीताल में अगला दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाने की घोषणा की, उसमें शामिल होने के लिए अनुमान के विपरीत 200 की जगह लगभग हजार हाथ उठ गए। बहरहाल आज जो आरक्षण की रक्षा के लिए परिसंघ की ओर से गंभीर आयोजन हुआ उसमें सबको सुनने के बाद यही लगा कि दलित नेताओं में निजीक्षेत्र में आरक्षण की कोई प्रभावी लड़ाई लड़ सकता है तो वह डॉ.उदित राज ही लड़ सकते हैं।

–लेखक बहुजन डाइवर्सिटी मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
संपर्क – 9654816191

परिसंघ के सदस्य बनें और सोसल मीडिया से जुड़े

डॉ0 उदित राज के नेतृत्व में चल रहे ऑल इंडिया परिसंघ की स्थापना 1997 में पांच आरक्षण विरोधी आदेशों की वापिसी के लिए हुआ और तब से लगातार संघर्ष करते हुए अनेको अधिकार सुरक्षित कराए। आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। आप परिसंघ के सदस्य बनकर इस आंदोलन को सहयोग कर सकते हैं। आप उपलब्धियों और गतिविधियों की लगातार जानकारी के लिए परिसंघ के सोसल मीडिया एकाउंट **www.facebook.com/aiparisangh** को लाइक करें। **twitter.com/aiparisangh** पर फालो करें। **All India Parisangh** यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। **Whatsapp No. : 9899766443** को अपने फोन में सेव करें और किसी भी जानकारी के लिए **parisangh1997@gmail.com** पर ईमेल करें। अधिक जानकारी हेतु सुमित मो. नं. **9868978306** पर सम्पर्क करें।

– सत्यानारायण, अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश, परिसंघ, मो . 9873988894

मूलनिवासी समाज में एकता तो ठीक, लेकिन घृणित काम-धन्धे कब छोड़ेंगे?

बाबा साहेब ने अपने एक उद्धरण में कहा था कि वह दिन दलित समाज के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जायेगा, जब ये सब रोटी-बेटी के लिये एक हो जायेंगे। लेकिन रोटी-बेटी के लिये नहीं तो वोट के लिये तो एक हो जाना चाहिये। उनके परिनिर्वाण को साठ साल हो चुके हैं, परन्तु आज तक स्वर्ण अक्षरो में लिखा जाने वाला वो दिन नहीं आया। न रोटी-बेटी के मामले में एकता हुई और न ही वोट के मामले में। सबसे दुखद पहलू यह रहा कि बाबा साहब का कोई घोषित उत्तराधिकारी नहीं था, जो उनके निर्वाण के बाद उनके विशाल काँरवे को संभाल पाता। जो थे, वे उनके अनुयायी थे, जिन्होनें जब तक जैसा चाहा, वैसे उनका काँरवा आगे बढ़ाया, बाद में अलग होते गये। उनके साथी भी अन्य राजनैतिक पार्टियों के लालच और अपने को सवर्णो जैसा दिखाने की चाहत में उन्हीं में जा मिले और कईयों ने तो सवर्ण जातियों में विवाह भी किये। मूलनिवासी समाज का आंदोलन, जो बाबा साहेब ने बड़े दुख-दर्द और तकलीफें सहन कर चलाया था, असमय ही निष्प्रभावी होने लग गया। सभी समाजों में जो भी थोड़े-बहुत पढ़े-लिखे उस समय बाबा साहेब की मेहरबानियों से बने, वे दिशा-विहीन हो गये और जातिगत संगठनों की जड़ें सींचने लग गये।

मूलनिवासी जातियों की एकता में आज भी एक बड़ा रोड़ा है। और वह है-कुछ जातियों के काम-धन्धे घृणित होना। बाबा साहेब ने काम-धन्धों के बारे में कहा था-

उनकी (दलितों की) मुक्ति का उत्तम मार्ग उच्च शिक्षा, अच्छा रोजगार और जीविका कमाने के उत्तम ढंगों में निहित है। यदि एक बार वे सामाजिक जीवन के स्तर पर अच्छी तरह प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो उनका सम्मान भी होगा और एक बार यदि वे सम्मान जनक बन जाते हैं तो कट्टर हिन्दुओं के उनके प्रति दृष्टिकोण में अवश्य परिवर्तन होगा और यदि ऐसा नहीं भी होता है तो दलितों के भौतिक हितों को कोई हानि नहीं होगी।'' मूलनिवासी समाज की समस्याओं पर बाबा साहेब का उक्त कथन कई जातियों का भविष्य निर्धारित करने की क्षमता रखता है, परन्तु यह सब तब है, जब उनके विचारों को माना जाये। बाबा साहेब के समर्थक बाबा साहेब को मानते हैं, लेकिन जहां उनके जातीय हित बाबा साहेब के सिद्धान्तों से टकराते हैं, वे अपने जातीय हितों को ही प्राथमिकता देते हैं। ऐसे उदाहरण बिरले ही होते हैं जब व्यक्ति ने जातीय हितों की अपेक्षा बाबा साहेब के सिद्धान्तों को प्रमुखता दी हो। मूलनिवासी समाज की कई जातियां आज भी आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या रखती है, जातिगत द्वेष रखती है और समय-असमय मरने-मारने पर उतारु रहती है। विभिन्न जातियों में बंटे मूलनिवासी ये नहीं समझ पाये हैं कि जातियां ब्राह्मणों की देन है, जिन्होंने दलितों में फूट डालने के लिये इनका निर्माण किया और स्वयं को सबसे उच्च रखा। कुछ ऐसे अन्तहीन झगडे पैदा कर दिये जिससे कि ये आपस में ही लड़ती-भिड़ती रहे और ब्राह्मणों का पेट भरता रहे। मुझे याद है कि टोंक शहर में जलझूलनी एकादशी पर हर साल हर समाज के मन्दिर से कृष्णजी की पालकी (डोळा) निकला करती थी। उस समय पचासों डोळे हो जाते थे। हर डोळे में यह प्रतियोगिता रहती थी कि कौन आगे निकले? इस बेहद ही मामूली और बेकार सी बात को लेकर कई समाजों में झगड़े हो जाते थे और लाठियां चल जाती थीं!! बैरवाओं के साथ अक्सर ही रैगर समाज के लोगों का झगड़ा होता था।

देखा जाये तो कृष्णजी को गुजरे हुए हजारों साल हो गये। हो सकता है कि उनके कार्यों की वजह से उनको याद किया जाता हो। लेकिन जब वे एक ही थे तो पहले चाहे किसी भी डोळे की मूर्तियों को स्नान करवाया जाये, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मूर्ख लोग सोचते-समझते थोड़े ही हैं! अब कृष्णजी के लिये तो मुसीबत खड़ी कर दी ना कि वे बैरवाओं का साथ दें कि रैगरों का? दोनो ही एससी के अलग। इसी प्रकार अनेक और भी तुच्छ कारण हैं जिनके चलते मूलनिवासी समाजों में एकता नहीं हो पाई है। समय की मांग को दलित युवाओं ने कई स्थानों पर समझा भी है और तदनुसार कार्य भी हो रहे हैं। कई संगठन जातीय संकीर्णता से ऊपर उठकर कार्यरत हैं और मूलनिवासियों में एकता के लिये कार्य रहे हैं।

लेकिन प्रत्यक्षतः कोई जीती मक्खी भी तो निगल सकता है। कोई एक तरफ तो नालियां और गटर साफ करने करे या चमड़े के कार्य को ही अपना पुश्तैनी धन्धा मान ले और वही करे भी, और साथ में यह भी चाहे कि वह सम्मानित जिन्दगी जीये, तो यह एक साथ होना मुश्किल है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वह अपना काम-धन्धा बदले और उसी के अनुसार जीवन जीये? मूलनिवासी समाज की कई जातियों ने जिस प्रकार हजारों कष्ट सहकर अपने-अपने पुश्तैनी काम-धन्धे छोड़े हैं, उसी प्रकार कुछ बची-खुची जातियां, जिनमें आज भी घृणित काम-धन्धे प्रचलित हैं, आखिर क्यों नहीं इस कलंक से मुक्ति पा लेती हैं ? इस कार्य के लिये कोई बाहर का व्यक्ति तो इनकी मदद करेगा नहीं, इनकी स्वयं की इच्छा शक्ति और साहस से ही यह कार्य हो पायेगा। अगर सामाजिक कलंक से मुक्त होना है, अन्य समाजों में अपनी प्रतिष्ठित छवि बनाना चाहते है और अपने बच्चों का अच्छा जीवन देना चाहते है तो घृणित काम-धन्धे छोड़ने ही पड़ेगे। आज के युग में अनेकानेक नये काम-धन्धों का बाजार बढ़ा है जिसमें कोई किसी की जाति नहीं पूछता, केवल योग्यता देखी जाती है। मूलनिवासी समाज के भी अनेक युवा इस प्रकार के कामा-धन्धों से जुड़े हैं, पर उनकी तादात इतनी कम है कि घृणित काम धन्धे करने वालों के ढ़ेर में दब कर रह जाती है। अतः नये काम-धन्धे अपनाने वालों की संख्या बढानी है। एक योजनाबद्ध तरीके से किसी भी नये कार्य की तलाश करने वाले युवाओं को घृणित काम-धन्धों में घुसने से रोककर तथा जो पुराने लोग कार्य करने वाले हैं, उनके लिये नये धन्धे में जगह तलाश करने से यह हो सकता है, परन्तु यह कठिन बहुत है। अन्य समाजों का उदाहरण सामने रखते हुए यह पहल तो करनी ही पड़ेगी और आज नहीं तो कल, ये कार्य करने ही पड़ेंगे, अन्यथा लोकतन्त्र और सरकार की सैंकड़ों योजनाओ का क्या फायदा जब आपके पूर्वज भी घृणित काम-धन्धा करते-करते स्वर्ग सिधार गये और आप तथा आपके बच्चे भी वही कार्य कर रहे हैं?

अतः समय के साथ-साथ दलित जातियों में एकता होनी आवश्यक है और इस एकता को और प्रगाढ़ कर सकती है एक पहल जो कि घृणित काम-धन्धों को छोड़ने के रुप में होनी है।

- श्याम सुन्दर बैरवा, भीलवाड़ा, 8764122431

***

राजस्थान के श्रीगंगानगर में खटीक सेना का संम्मेलन संम्पन्न

खटीक सेना देश के 12 प्रदेश में प्रदेश से लेकर जिला स्तर की कमेटी का गठन किया जा चुका हैं। खटीक सेना संपूर्ण भारत वर्ष में जमनि स्तर पर पहुंच कर बाबा साहब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकारों को बताने एवं उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा और समाज के हित में जो भी अधिकार दिए हैं उसको पाने के लिए देश भर में एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेगा। दिनांक 30 जुलाई, 2017 को राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर गाव में सभा को संबोधित करते हुए संपूर्ण समाज के लोगों को बताया की डॉ. अम्बेडकर ने 1950 में देश के सामने जब संविधान रखा तो उस वक्त देश में हाबी मनुवादी प्रवृत्ति के लोगों द्वारा इस देश के मूलनिवासियों को जो 5 हजार वर्षो तक गुलाम बना कर राज करता रहा, जिससे संपूर्ण मुलनिवासी मानिसक रूप से विक्लांग हो गये थे। इस विक्लांगता को दूर करने के लिए समस्त दलित समुदाय को संविधान में आरक्षण का प्रावधान बनाया। जिससे शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकसीत हो सके। इस आरक्षण को देने के लिए बाबा साहब ने खून के आसु तक बहा दिये ऐसे संघर्ष भरे पल में बीबी और बच्चे लाईलाज दम तोड देते है, लेकिन बाबा साहब संपूर्ण भारत वर्ष के दबे कुचले लोगों के जीवन को प्रतिबिंब के रूप में महसूस करते हुए अपने कदम को रुकने नहीं दिए। अंत में संवैधानिक आरक्षण रूपी अधिकार समाज को दे ही दिया। जिससे समाज की चौतरफा तरकि हुई।

इन्ही सताई हुए जातियों की कड़ी में यह खटीक समाज भी आती है। जिस को बाबा साहब ने संपूर्ण भारत वर्ष में खटीक जाति को अनुसूचित जाति में जगह दिया, कि पूरे भारत में खटीक समाज का भी समाजिक, शैक्षणिक व मानसिक रूप से विकास हो सके जिसमें से भारत देश को आजाद हुए 70 वर्ष बीत गए लेकिन आज भी खटीक समाज को केवल देश के 12 प्रदेश में अनुसूचित जाति में रखा गया है और जिन लोगों को आरक्षण का फायदा मिला जिसकी वजह से हजारों अधिकारी, कर्मचारी एवं वर्तमान समय में देखा जाए तो खटीक समाज के 8 एम.पी. (लोकसभा सदस्य) और 18 विधायक (विधान सभा सदस्य) बन पाए, और जिन जिन प्रदेशों में आरक्षण का लाभ नहीं मिला उन प्रदेशों में एमपी, विधायक की तो बात छोड़िए पार्षद भी नजर नहीं आते।

बहुत दुःख का विषय है कि देश में मनुवादियों ने खटीक समाज पर ज्यादा मानसिक व सामाजिक विकास रोकने के लिए उनकी आंखो में काली पट्टी बांधकर देवी-देवताओं की पूजा-पाठ में लिप्त कर दिया। जिससे समाज अपनी हकीकत, इतिहास एवं औकात को भूल गया है। यहां तक नहीं बल्कि देश के ब्राह्मणवादियों ने समाज को 365 गोत्रों (जातीय टुकड़ो) में बांटा यह केवल जातियों में नहीं बांटा हम अपने शब्दों मे समाज के बच्चे-बच्चे के जीवन में विष फहलाने का काम किया। जिसमें से कुछ जातियां इस प्रकार है। नावरिया, सामरिया, चक, चौहान, सोनकर, सोलंकी, परेवा, बुंदेला, पहाड़िया, खिची, चेतीवाल, बड़गुजर इत्यादी।

खटीक सेना के महासिचव मा. इन्द्रेश चन्द्र खटीक ने हजरों की संख्या को संबोधित करते हुए कहा की हमारे समाज को जिन मनुवादियों ने ऐसी जर-जर हालत में लाने का काम किया है उसका जवाब हम पूरे देश के सामने देगें। जिन-जिन प्रदेशों में खटीक समज को संविधान के मुताबिक अनुसूचित जाति में रखा नहीं गया हैं। उन-उन प्रदेशों में अतिशीघ्र अनुसूचित जाति में लाने के लिए प्रदेश व देश स्तर पर आंदोलन करेगें और हम मनुवादियों के द्वारा दिए गए गोत्रों को अतिशिघ्र जड़ से खत्म कर देगें। हम सब नाम आगे या पीछे या बीच में खटीक शब्द जोड़कर देश में एकजुट का पताखा फरायेंगे। इस सभा में उपस्थित मा. ब्रजीलाल सोनकर, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, विजेन्द्र बड़गुजर, राजेन्द्र चेतीवाल, लक्ष्मी नारायण सामरिया, सोहन लाल खटीक, देव किशन दायमा, गोपाल पहाड़िया, राकेश चंदेल एवं नरेश खिचीं उपस्थित रहे।

***

भारतीय मीडिया की नजर में दलित-आदिवासी और सोसल मीडिया की उपयोगिता

जब हम मीडिया में दलित मुद्दों की बात करते हैं तब सबसे पहला सवाल यही आता है कि मीडिया में दलित समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा सामाजिक मुद्दा और देश का मुद्दा क्यों नहीं बन पाता? जबकि इनकी संख्या देश में सबसे ज्यादा है। किसी कार्यक्रम, धरना-प्रदर्शन का कोई भी बैनर, जिस पर बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर या बहुजन समाज से जुड़े हुए किसी भी महापुरुष की तस्वीर लगी हो, या फिर उस पर दलित शब्द लिखा हो, वह तुरंत दलित समाज का मुद्दा बन जाता है, फिर वह देश का, समाज का मुद्दा नहीं रह जाता। भारतीय मीडिया इस वर्ग को इंसान के तौर पर नहीं, एक अलग किस्म के समूह के तौर पर देखता है। जैसे यह भारतीय समाज के बीच का हिस्सा नहीं है।

मीडिया की भाषा

आए दिन अखबारों की सुर्खियों में देखने को मिल जाता है कि दलित महिला का बलात्कार, दलित को मंदिर में नहीं घुसने दिया, अम्बेडकर की रिंग टोन बजने पर दलित युवक को पीटा, दलित सांसद ने कहा, दलित मंत्री ने कहा आदि। जब मीडिया इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है तो असल में वह एक खास वर्ग को यह भी संदेश दे रहा होता है कि तुम अपना काम करते रहो, तुम आराम से रहो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यह तुम्हारा मुद्दा नहीं है। यह देश का मुद्दा नहीं है। ऐसा कह कर मनुवादी व्यवस्था की समर्थक मीडिया दलित समाज को डराने की कोशिश भी करता है। वह दलित समाज को आगाह करता है कि देख लो.. तुम विरोध करोगे तो मारे जाओगे, तुम्हारी बहन-बेटियों के साथ बलात्कार होगा, इन मंदिरों में घुसने की हिमाकत मत करना नहीं तो तुम पीटे जाओगे, ज्यादा अम्बेडकर-अम्बेडकर मत चिल्लाओ नहीं तो हम तुम्हारा भी वही अंजाम करेंगे। यदि ऐसा न होता तो मीडिया में यह भी छपता कि ब्राह्मण लड़की के साथ बलात्कार हुआ। जबकि बलात्कार की शिकार हर जाति और धर्म की महिलाएं होती हैं। यह है मीडिया का चेहरा और दलित मुद्दों को लेकर उसके काम करने का तरीका।

दलित मुद्दों को देखने का नजरिया

जब दिल्ली में अन्ना आंदोलन हुआ तो जंतर मंतर पर दिन भर मीडिया का जमावड़ा लगा रहा, महीनों तक टीवी चैनलों और अखबारों में खबरें चलती रहीं, लगा कि जैसे बस देश सुधर गया। आंदोलन का अंजाम क्या हुआ सबके सामने है? अब दलितों के उत्पीड़न की घटनाओं को देखो। ऊना की घटना के बाद गुजरात में दलितों का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, महीनों तक यह चला लेकिन मीडिया ने इस आंदोलन को कैसे दिखाया और कितना दिखाया यह आपके सामने है। सहारनपुर की घटना पर भारतीय मीडिया का रवैया किसी से छुपा नहीं है। मीडिया ने कभी भी जातिवाद जैसी बड़ी सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए मुहिम नहीं चलाई। अगर भ्रष्टाचार देश का नासूर बना हुआ है और उसको खत्म करने को लेकर मीडिया ने दिन-रात एक कर दिया था तो क्या जातिवाद देश के लिए नासूर नहीं है। क्या मीडिया को इस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए आंदोलन नहीं छेड़ देना चाहिए? जैसे उसने निर्भया मामले में और अन्ना आंदोलन के दौरान किया।

दलित-आदिवासी की भागीदारी न होना भी कारण

जिस विषय पर हमलोग बात कर रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है, जिसको समझे बिना मीडिया के इस सारे खेल को समझा नहीं जा सकता है। वह सवाल है मीडिया में दलित/आदिवासी समाज के प्रतिनिधित्व का। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मीडिया में दलित/आदिवासी समाज का एक प्रतिशत प्रतिनिधित्व भी नहीं है। यानि इसमें पैसा एक खास वर्ग का लगा है और इसमें काम करने वाले 90 प्रतिशत लोग सामान्य वर्ग से हैं।

दलित/आदिवासी महापुरुषों के प्रति नजरिया

अम्बेडकर जयंती वंचित तबके के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है। असल में यह पूरे देश के लिए उल्लास का विषय होना चाहिए लेकिन पूरा देश नहीं मानता। देश का एक बड़ा हिस्सा बाबा साहेब को मानता है और यह दिन उनके लिए बहुत अहम है। इसकी संख्या तकरीबन 30-40 करोड़ है। यह समाज भी टीवी देखता है। बावजूद इसके मीडिया में यह आज भी बैन है। मीडिया इसे जिस स्तर पर चाहिए सेलिब्रेट नहीं करती है। जो मीडिया करवा चौथ और भाई दूज तक की खबर पर पैकेज बनाता है, वही मीडिया बाबा साहेब की जयंती की अनदेखी करने की कोशिश करता है। बिरसा मुंडा के बारे में मीडिया क्यों चुप्पी साधे रहती है, जबकि देश का आदिवासी समाज उन्हें पूजता है और जिनकी विचारधारा पर झारखंड जैसा राज्य बनाया गया। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, जिस दंपत्ति ने स्त्री शिक्षा को लेकर इतना बड़ा काम किया, मीडिया उन्हें क्यों नहीं याद करती है? दलित-आदिवासी और वंचित तबके के ऐसे सैकड़ों नायक हैं जिनका नाम लिया जा सकता है, लेकिन यह मीडिया उन्हें याद नहीं करता।

हर साल अगस्त की 15 तारीख को देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आजादी की अनुभूति का अद्भुत नजारा होता है। टीवी चैनलों और अखबारों में अगस्त के पहले हफ्ते से ही तमाम स्पेशल रिपोर्ट की बाढ़ आ जाती है लेकिन उस मौके पर भी इस देश का मीडिया दलित और आदिवासी समाज से जुड़े नामों को याद करने से परहेज करता है। भगत सिंह की बात होती है, गांधीजी की बात होती है, चंद्रशेखर आजाद, नेहरू तक की बात होती है, यहां तक कि देश के जिन सैनिकों को परमवीर चक्र मिला होता है, उनकी भी बात होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन सवाल उठता है कि बिरसा मुंडा की बात क्यों नहीं होती, तब 32 अंग्रजों को मार गिराने वाली ऊदा देवी पासी की बात क्यों नहीं होती, अंग्रेजों को नाकों चने चबवा देने वाला शहीद बुद्धु भगत की बात क्यों नहीं होती, वीरा पासी (50 हजार के इनामी) की बात क्यों नहीं होती, पलामू में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले निलाम्बर और पीताम्बर बंधुओं की बात क्यों नहीं होती, जिन्होंने अंग्रेजों को इतना परेशान कर दिया कि उन पर अंग्रेजों को 50 हजार का इनाम रखना पड़ा, ऐसे वीर बांके चमार की बात क्यों नहीं होती, चौरी-चौरा के नायक रमापति चमार की बात क्यों नहीं होती? जिस तरह भगत सिंह और आजाद को हीरो बनाकर पेश किया जाता है, उधम सिंह को उतनी इज्जत क्यों नहीं मिलती। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात तो की जाती है लेकिन झलकारी बाई के योगदान को उस गहराई से क्यों नहीं याद किया जाता?

बाबा साहेब मीडिया की ताकत और जरूरत दोनों को समझते थे। चूंकि उस समय जो पत्र-पत्रिकाएं निकल रही थी वह वंचित समाज के मुद्दों और समस्याओं की ओर से बिल्कुल आंखें मूंदे हुए थी। आज जब यह हाल है तो आप समझ सकते हैं कि तब क्या हाल रहा होगा। तो भारत के वंचित समाज के मुद्दों को उठाने के लिए बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर को एक अखबार शुरू करना था। अखबार का नाम था 'मूकनायक'। अखबार के प्रचार - प्रसार की बात आई। उसी समय बाल गंगाधर तिलक 'केसरी' नाम का अखबार निकाल रहे थे। डॉ. अम्बेडकर ने 'केसरी' अखबार में 'मूकनायक' के प्रकाशित होने का विज्ञापन छपवाने के लिए संपर्क किया, लेकिन बताया जाता है कि तिलक ने बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा निकाले जाने वाले अखबार का विज्ञापन तक छापने से इंकार कर दिया था। आप सोच सकते हैं कि 'केसरी' जैसे अखबार जिन्होंने वंचित समाज के योग्य व्यक्ति द्वारा दिए गए विज्ञापन को प्रकाशित नहीं किया वह दलितों के हितों से जुड़े मुद्दों को कितनी अहमियत देता रहा होगा?

कांशीराम जी बामसेफ के बैनर तले सामाजिक तौर पर काफी सक्रिय हो चुके थे। देश भर में लोग बामसेफ से जुड़ रहे थे। बोट क्लब पर बामसेफ का पहला अधिवेशन हुआ। देश भर से हजारों लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे। भव्य आयोजन किया गया, लेकिन दूसरे दिन के अखबारों में इसकी एक लाइन खबर भी नहीं थी। बामसेफ से जुड़े लोगों को काफी बुरा लगा कि हमने इतना बड़ा सम्मेलन किया लेकिन इसकी कोई रिपोर्ट नहीं छपी। बामसेफ के आंदोलन की बात लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रेस कांफ्रेंस करने का फैसला किया गया। प्रेस क्लब बुक किया गया। तारीख और समय के साथ सभी अखबार के दफ्तरों में इसकी सूचना दे दी गई। नियत समय पर कांशीराम जी और उनके एक अन्य साथी प्रेस क्लब पहुंच गए। एक घंटा बीता, दो घंटा बीता, तीन घंटा बीता लेकिन कोई भी मीडियाकर्मी प्रेस कांफ्रेंस में नहीं पहुंचा। गजब तो यह हुआ कि प्रेस क्लब में रोज शाम को खाने-पीने के लिए मीडियाकर्मियों की भीड़ लगी रहती है लेकिन उस दिन तमाम मीडिया वाले प्रेस क्लब आए ही नहीं।

स्थिति आज भी बहुत नहीं बदली है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर जाकर देखिए, इस समाज के लोग आए दिन अपनी मांगों और समस्याओं के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं। जाहिर है कि सारी खबरों को दिखाना संभव नहीं है। भगाणा गांव, हिसार, हरियाणा के दलित जातिवादी गुंडों के उत्पीड़न का शिकार होकर गांव से पलायन कर गए। उनकी बेटियों का बलात्कार किया गया। सालों तक वे इंसाफ के लिए जंतर-मंतर पर धरना देते रहे लेकिन उनका दर्द सुनने के लिए मुख्यधारा का कोई मीडिया नहीं पहुंचा। हां, जब उन्होंने उसी जंतर-मंतर पर इस्लाम अपना लिया तो हलचल जरूर हुई थी।

मीडिया की नजर में अजा/जजा परिसंघ

डॉ. उदित राज के नेतृत्व में चल रहे अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ अपनी तरह का एकमात्र देश का सबसे बड़ा संगठन है जो दलित अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हैं। इसके आंदोलन के दबाव के कारण ही तीन संवैधानिक संशोधन हुए और काफी हद तक अनुसूचित जाति/जन जाति को मिल रहे आरक्षण का अधिकार बरकरार रह पाया। परिसंघ ने ही बहुजन लोक पाल बिल में आरक्षण का मुद्दा उठाया और इसका प्रावधान भी हुआ। परिसंघ के आंदोलन के कारण ही निजी क्षेत्र में आरक्षण का राष्ट्रीय मुद्दा बना। 4 नवंबर, 2001 को लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। दलित अधिकारों पर प्रतिवर्ष रामलीला मैदान, दिल्ली में लाखों लोगों की रैली की जाती है। इसके अलावा हजारों लोगों का धरना-प्रदर्शन व सम्मेलन चलते ही रहते हैं लेकिन भारतीय मीडिया की नजर में परिसंघ की न के बराबर अहमियत है। देश के इतने बड़े तबके के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले संगठन व व्यक्ति को भारतीय मीडिया अपेक्षित स्थान नहीं देती।

सोसल मीडिया ही एकमात्र विकल्प

प्रश्न उठता है कि अखिर ऐसे में हम क्या करें। पहला विकल्प है कि हम अपना मीडिया बनाएं, जिसमें करोड़ों रूपये का खर्च आएगा जो हमारे बस की बात नहीं है। मान लिया जाए कि मीडिया अपना स्थापित भी कर लें तो उसके बाद भी ज्यादा संभावनाएं हैं कि विज्ञापन आदि जिससे मीडिया हाउस चलते हैं, हमें मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि ज्यादातर विज्ञान देने वाली कंपनियों के स्वामी तथाकथित सवर्ण जाति से ही हैं। ऐसे में एकमात्र विकल्प बचता है सोसल मीडिया का, जो वर्तमान समय में बहुत प्रभावी और सस्ता माध्यम है। एक स्मार्ट फोन जो 4-5 हजार रूपये की कीमत से शुरू हो जाता है, पर फेसबुक, ट्वीटर, व्हाट्सअप, यूट्यूब आदि के माध्यम से अपनी बात सेंकडों और मिनटों में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचायी जा सकती है। इसलिए परिसंघ के सभी पदाधिकारियों व शुभचिंतकों से आग्रह है कि अधिक से अधिक सोसल मीडिया का इस्तेमाल करें और परिसंघ के ट्वीटर, फेसबुक से जुड़ें व यूट्यूब चैनल को सब्सिक्राइब करें।

***

राष्ट्रपति चुनाव का सामाजिक संदेश

डॉ. उदित राज

जैसा कि अपेक्षित था, राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में राजग की ओर से प्रत्याशी घोषित किए गए रामनाथ कोविंद आसानी से जीत हासिल करने में समर्थ रहे। इस आसान जीत में राजग के बाहर के भी कुछ राजनीतिक दलों की भूमिका रही। रामनाथ कोविंद को अनुमान से अधिक मत मिले। उनके निर्वाचन की घोषणा होते ही विपक्षी दलों के कई नेताओं के साथ अनेक प्रमुख देशों ने भी उन्हें बधाई दी। देश के सर्वोच्च पद पर उनके निर्वाचन को भारतीय लोकतंत्र की खूबी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि उनके नाम की घोषणा के बाद इस तरह की चर्चा शुरू हो गई थी कि देश को दूसरा दलित राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। सच तो यह है कि इस बात का प्रचार तभी हो गया था जब भाजपा की ओर से रामनाथ कोविंद के नाम की घोषणा की गई थी। राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम न तो चर्चा में था और न ही उन्हें संभावित प्रत्याशी के तौर पर देखा जा रहा था। उनके नाम की घोषणा होने के बाद संप्रग का नेतृत्व कर रही कांग्रेस ने बाध्य होकर दलित उम्मीदवार का ही चयन किया। उसने मीरा कुमारी को कोविंद को चुनौती देने के लिए आगे किया। कांग्रेस के फैसले के चलते राष्ट्रपति चुनाव दलित बनाम दलित का सवाल बन गया। जल्द ही ऐसे सवाल उठे कि आखिर उम्मीदवार की पहचान दलित प्रत्याशी के तौर पर क्यों? इसी के साथ दलित प्रत्याशी के राजनीतिक और सामाजिक महत्व पर भी चर्चा ने जोर पकड़ा।

भले ही राष्ट्रपति के पास एक सीमित कार्यकारी ताकत हो, लेकिन यह देश का सर्वोच्च पद है। इसके साथ ही साथ वह संविधान का संरक्षक एवं सेना का प्रमुख भी होता है। जबसे राज्य का चरित्र कल्याणकारी हुआ है। तबसे दुनिया के तमाम ऐसे समाज हैं जो कुछ न कुछ उन वर्गो के लिए करते रहते हैं जो या तो कमजोर हैं या फिर जिनका प्रतिनिधित्व कम है। कभी-कभी समानता, न्याय और शांति का संदेश देने के लिए भी ऐसे कदम उठाने जरूरी हो जाते हैं। कई बार ऐसे कदम प्रतीकात्मक करार दिए जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि प्रतीकों की भी अपनी महत्ता होती है-भारत सरीखे लोकतंत्र में और भी। भारतीय समाज की परिस्थितियां दुनिया के दूसरे देशों से भिन्न हैं। दूसरे देशों में जातियों के आधार पर असमानता और भेदभाव जैसी समस्याएं नहीं हैं। जिनके मन में यह सवाल उठा अथवा जिन्होंने यह सवाल उछाला कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार दलित क्यों उन्होंने शायद यह माना होगा कि जब जाति बीते कल की बात होती जा रही है तब फिर उसे इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। हर कोई अपनी परिस्थिति और नजरिये के हिसाब से सोचता है। जिन्हें यह लगता है कि राष्ट्रपति प्रत्याशी की जाति को

रेखांकित नहीं किया जाना चाहिए उन्हें इससे अवगत होना चाहिए कि हमारे समाज में असमानता और भेदभाव की एक बड़ी वजह जाति ही है। जाति को बीती बात बता रहे लोग अगर दलितों और अतिपिछड़ों की जिंदगी के कुछ लम्हे जिए होते तो शायद उनकी सोच कुछ और बनती। एक क्षण के लिए सोचिए कि उन पर क्या गुजरती होगी जो पीढ़ियों से मैला उठाने, दूसरों के कपड़े धोने, मृत जानवरों की खाल उतारने अथवा उन्हें दफनाने जैसे काम करते हैं?

जून 1893 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में प्रथम श्रेणी का टिकट लेकर रेल से सफर कर रहे थे तो उन्हें कहा गया कि तीसरी श्रेणी में चले जाएं, क्योंकि वह श्वेत नहीं हैं। चूंकि उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था इसलिए वह सहमत नहीं हुए और उन्हें जबरदस्ती रेलवे स्टेशन पर उतार दिया गया। वह इस अपमान को सह न सके और पूरी रात स्टेशन पर चिंता करते रहे और और अंत में उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ने की ठानी। गांधी जी के साथ जो हुआ उससे कई गुना ज्यादा असंख्य दलितों और पिछड़ों के साथ हजारों वर्षों से हो रहा है और फिर भी वे बर्दाश्त करते आ रहे हैं। अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो दूसरे दलित के तौर पर राष्ट्रपति पद पर रामनाथ कोविंद का निर्वाचन दलित वंचित समुदाय को संबल देने और साथ ही उन्हें प्रेरित करने वाला भी है। प्रत्येक व्यवस्था का यह दायित्व बनता है कि वह उन आवाजों को सम्मान दे जो दबी और कुचली है। इससे न केवल उनका भला होगा, बल्कि जो संपन्न और समर्थ हैं उनकी भी मानसिकता में सकारात्मक बदलाव आएगा। असमानता और भेदभाव वाले समाज में सबसे जरूरी होता है लोगों की मानसिकता बदलना।

भारत हजारों जातियों और कई संप्रदायों का समाज है। जब तक सबको भागीदारी नहीं दी जा सकती तब तक कभी दलित, कभी पिछड़ा, कभी महिला आदि वर्गो में से किसी को समय-समय पर प्रतिनिधित्व देना ही चाहिए। अगर आज सभी को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में भागीदारी मिल गई होती तो शायद जाति या पंथ को कहीं कम महत्व मिल रहा होता। दलित राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का निर्वाचन एक कोशिश है कि एक समय ऐसा आए कि कोई भी ऐसा महसूस न करे कि वह उपेक्षित है। हमारे समाज में ऐसा भाव आ जाए तो इससे तमाम चीजें बगैर जाति-पंथ की पहचान से तय होने लगेंगी। निरुसंदेह हमें अभी ऐसे वक्त का इंतजार है। इसी तरह उस दिन का भी इंतजार है जब लोग ईमानदारी से सोचें कि वास्तव में जातियों में बंटने से हम गुलाम हुए और आज भी अगर पीछे हैं तो मुख्य कारण यही है।

हाल में दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक सेमिनार हुआ। उसमें बोलते समय मुझे इजरायल का स्मरण हो आया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय इजरायल में ही थे। मुझे कहना पड़ा कि अगर हमारा समाज इजरायल के समाज की तरह संगठित होता तो एक असफल देश पाकिस्तान की बार-बार धृष्टता करने की हिम्मत न होती। दलित समाज से दूसरे राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का निर्वाचन समाज को संगठित करने की कोशिश के साथ भारतीयता की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास भी है। जब तक जाति है और मान-सम्मान में उसका प्रभाव है तब तक वैसे कदम उठाए जाते रहने चाहिए जैसे रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति निर्वाचित करने के लिए भाजपा की ओर से उठाए गए। उनके निर्वाचन का राजनीतिक महत्व तो है ही, एक सामाजिक महत्व भी है और उसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।

- लेखक लोकसभा के सदस्य हैं , दैनिक जागरण में 21 जुलाई,2017 को प्रकाशित लेख

***

Karnataka Caste Census : Hailed for Ambedkar meet, CM keen to release findings

We want to make the report public but there are hindrances : Siddarmaiah

Having drawn appreciation from a vast section of Dalits for organising a mega conference on Dr B R Ambedkar in Bengaluru recently, Karnataka Chief Minister Siddaramaiah has expressed keenness to release results of a caste census conducted two years ago in a bid to consolidate the community's support. The Socio Educational and Economic Census, a pet project of Siddaramaiah, was sanctioned in 2013 and completed in 2015. But the results have been under wraps, reportedly due to opposition from a section of Dalit leaders within the ruling Congress and dominant castes like Lingayats in north Karnataka.

According to some Dalit leaders, the opposition to release of the report is from a section in the community known as "right Dalits", anecdotally shown as enjoying most benefits in the society over the poorer "left Dalits". Lingayats, it is learnt, are opposed to the release as leaked sections of the report have shown their numbers as being substantially lower than the current estimate in which they account for 17 per cent of the state's six crore population.

Leaked sections of the report have shown Dalits to be the largest community in the state. According to current estimates, Scheduled Castes and Scheduled Tribes account for nearly 23 per cent of Karnataka's population. The Scheduled Castes or Dalits are, however, divided into "right dalits" (Holayas who follow Babu Jagjivan Ram) and "left Dalits" (Madigas who follow Ambedkar). The "left Dalits" feel hard done by the "right Dalits" in benefiting from reservations in government jobs and education and have been demanding release of the caste census to throw light on their situation. There has been speculation that the Siddaramaiah government is likely to release the findings ahead of the 2018 Assembly polls.

"After the census report comes, we will be able to create programmes for the downtrodden and give preference to them in our planning. We want to make the report public but there are hindrances to it from those opposed to social justice. They accuse me of engaging in caste politics. Is it caste politics to try and understand the situation of people?" Siddaramaiah said on the final day of the Ambedkar meet. According to sources in the government, much of the opposition to the release of the findings is from within Congress in which "right Dalits" occupy important positions.

"The biggest opposition is not from Lingayats, but from Congress leaders from the community," the sources said. Senior Congress leaders like Mallikarjun Kharge, G Parameshwara and H C Mahadevappa are "right Dalits". The party currently lacks any major leader from the left group other than Social Welfare Minister H Anjaneya and former union minister K H Muniyappa. Incidentally, the BJP carried out a social engineering exercise among Dalits in Karnataka a decade ago to exploit the weakness in the Congress support base within the community. In the 2008 elections, BJP won 21 of the 36 seats reserved for SC candidates in Karnataka. In 2013, Congress won 15 SC seats, while BJP and JDS won seven and 12, respectively.

Madiga activist B Nagaraj said at the Ambedkar conference, "Left Dalits have two major demands if Congress seeks their support — one is the release of the caste census report and the other is implementation of Justice A J Sadashiva commission recommendations." Justice A J Sadashiva commission report of 2012 recommends internal reservations among Dalits taking into account backwardness and right-left groupings.

***

Dr. Udit Raj, Member of Parliament introduced SCP/TSP Private Member Bill in Lok Sabha

Dr. Udit Raj, Member of Parliament introduced a Private Member Bill on 21st July, 2017 namely "The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Sub Plans (Budgetary Allocation and Special Schemes) Bill, 2017." There are following provisions in the Bill -

(1) The Central Government shall, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, make separate budgetary allocation for the welfare and development of persons belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, in proportion to their population.

(2) The budgetary allocations so earmarked under sub-section (1) shall be spent only on special schemes in such manner, as may be prescribed.

(3) The budgetary allocations under the Scheduled Castes Sub Plan and Tribal Sub Plan shall not be diverted for any other purposes or allowed to lapse.

(4) For the purposes of this Act, the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India shall be the nodal Ministry for the Scheduled Castes Sub Plan and the Ministry of the Tribal Affairs shall be the nodal Ministry for Tribal Sub Plan.

(5) The Ministry of Social Justice and Empowerment and the Ministry of Tribal Affairs shall present separate Annual Budgets and Performance Budgets for the Scheduled Castes Sub Plan and Tribal Sub Plan, respectively.

(4) Whoever contravenes the provisions of sub-sections (2) or (3) of section 3 shall be guilty of wilful and deliberate act of dereliction of duty and shall be punished under section 4 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 after fixing the individual responsibility.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS OF THE BILL

The legislative efforts undertaken to close the development gap between Dalits and Adivasis and other date back to 1950, when the Constitution provided opportunities for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the areas of education, employment in public services and electoral seats through the policy of reservation. From economic point of view, the most important policies approved so far are the Tribal Sub Plan (TSP) and the Special Component Plan (SCP), now called Scheduled Castes Sub Plan (SCSP), executive budget policies, according to which funds and resources are to be reserved across Central Ministries and Departments in the State Governments in proportion to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes population at the National, as per the current census data.

However, close scrutiny of the current situation reveals that these two policies have not been implemented effectively. The money earmarked under these policies is diverted for general scheme and does not go for funding of the schemes, exclusively for the benefit of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. It is not surprising that Dalits and Adivasis still remain far away from mainstream development in the country. The literacy gap is still quite high and the dropout rate is still high. The rate of infant mortality and child mortality under five is higher among the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes than among other social group; the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are still less equipped with the basic requirements for human survival like water and power supply facilities, latrines, sewarage, houses, etc. and poverty is still very rampant among them.

In fact, positive and substantial changes require making appropriate allocation of funds compulsory, their distribution timely and focused and effective management of the funds for the welfare of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes. Hence, there is a need to introduce a new piece of legislation with the objective of achieving the holistic and speedy economic development of these communities. In order to ensure speedy economic development of the persons belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, it is proposed to give statutory back up to the SCSP and TSP and a strict monitoring on their implementation, without diversion of funds earmarked for welfare of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

***

सांसद, डॉ. उदित राज जी ने एससीपी एवं टीएसपी से संबंधित निजी बिल लोक सभा में पेश किया

लोक सभा के मानसून सेसन में 21 जुलाई, 2017 को डॉ. उदित राज जी ने ने 'अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां उप-योजना (बजटीय आबंटन और विशेष योजनाएं) विधेयक, 2017' पेश किया और इस बिल में निम्नलिखित प्रावधान किए जाने का उल्लेख किया गया है –

(1) केन्द्र सरकार, संसद द्वारा विधि द्वारा सम्यक् विनियोग के पश्चात् अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समुदायों के लोगों के कल्याण और विकास के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में बजटीय आबंटन करने के लिए पृथक-पृथक योजना बनाएगी।

(2) उप-धारा (1) के अन्तर्गत इस प्रकार नियत बजटीय आबंटन विशेष योजनाओं पर ही, ऐसी रीति से जो विहित की जाए, व्यय किया जाएगा।

(3) अनुसूचित जातियां उप-योजना और जनजातीय उप-योजना के अन्तर्गत बजटीय आबंटन का न तो अन्यत्र उपयोग किया जाएगा और न ही वह व्ययगत होगा।

(4) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जातियां उप-योजना के लिए भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नोडल मंत्रालय होगा तथा जनजातीय उप-योजना के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय नोडल मंत्रालय होगा।

(5) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जातियां उप-योजना और जनजातीय उप-योजना के लिए क्रमशः पृथक वार्षिक बजट और निष्पादन बजट प्रस्तुत करेंगे।

(6) जो कोई भी धारा 3 की उप-धारा (2) अथवा (3) में अंतर्विष्ट उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह जानबूझकर और सोच-समझकर कर्तव्य की उपेक्षा करने के कृत्य का दोषी होगा और व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय किए जाने के पश्चात् अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 4 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

दलितों एवं आदिवासियों तथा अन्य लोगों के बीच विकास के अंतर को पाटने के लिए विधायी प्रयास 1950 से ही शुरू हुए थे जब संविधान में आरक्षण नीति के माध्यम से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा, लोक सेवाओं में रोजगार तथा निर्वाचन सीटों के क्षेत्रों में अवसर प्रदान किए गए थे। आर्थिक दृष्टि से अब तक अनुमोदित सर्वाधिक महत्वपूर्ण नीतियां हैं जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) तथा स्पेशल कंपोनेंट प्लान (एससीपी), जिसे अब अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) के नाम से जाना जाता है, संबंधी कार्यकारी बजट नीतियां जिनके अनुसार मौजूदा जनगणना आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के विभागों में निधियां एवं संसाधन सुरक्षित रखे जाते हैं। तथापि मौजूदा स्थिति की गहन समीक्षा करने पर पता चलता है कि इन दोनों नीतियों को कारगर ढंग से कार्यान्वित नहीं किया गया है। इन नीतियों के तहत निर्धारित की गई धनराशि का अन्यत्र सामान्य योजना में उपयोग कर लिया जाता है और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए विशेष रूप से बनाई गई योजनाओं के निधियन हेतु प्रयोग में नहीं लाई जाती। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दलित और आदिवासी देश में विकास की मुख्यधारा से अब भी बहुत दूर हैं। साक्षरता का अंतर अभी भी काफी अधिक है और बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की दर अभी भी काफी अधिक है। शिशु मृत्यु दर तथा पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर समाज के अन्य वर्गों की तुलना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में अधिक है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पास अभी भी मानव जीवन के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं जैसे जल एवं विद्युत आपूर्ति सुविधाओं, शौचालयों, मलजल निकास, मकानों इत्यादि का अभाव है और उनमें निर्धनता अभी भी व्याप्त है। वास्तव में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए लिए निधियों का उपयुक्त आवंटन अनिवार्य बनाकर उनका समय से वितरण तथा प्रभावी प्रबंधन कर ही सकारात्मक एवं महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए जा सकते हैं। अतः इन समुदायों के समग्र एवं तीव्र आर्थिक विकास को हासिल करने के उद्देश्य से एक नया विधान लाए जाने की आवश्यकता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों का तीव्र आर्थिक विकास सुनिश्चित कराने की दृष्टि से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निर्धारित निधि का अपयोजन किए बिना अनुसूचित जातियां उप-योजना और अनुसूचित जनजातियां उप-योजना के लिए कानूनी समर्थन देना और उनके कार्यान्वयन की सख्त मानीटरिंग करने का प्रस्ताव है।

***

Islam's reform: Way to go

Can passages of the Quran be cherry-picked — to embrace what is appealing and to skirt around what is not ? That is the question

-Javed Anand

In his article on how religions evolve ('Let's talk to the Book', IE, July 15), Ramesh Venkataraman makes the interesting proposition that the ongoing debate on triple talaq in the country signals the welcome stirring of the reform process in Indian Islam. In parting, he should perhaps have urged Indian Muslims to speed up a bit. For in their slow march forward Indian Muslims are way behind their co-religionists elsewhere who have been asking tough questions of their Book, making bold demands of their faith and its followers. Not surprisingly, Muslims committed to universal human rights, gender justice, non-discrimination between citizens on grounds of religion etc face difficulties with many a Quranic verse.

On gender justice, a good example is the oft-quoted verse 4:34 (Venkataraman quotes it partially): "Men are the protectors and maintainers of women, because Allah has given the one more (strength) than the other, and because they support them from their means. Therefore the righteous women are devoutly obedient, and guard in (the husband's) absence what Allah would have them guard. As to those women on whose part they fear disloyalty and ill-conduct, admonish them (first), (next), refuse to share their beds, (and last) beat them (lightly)." Venkataraman quotes the philosopher Anthony Appiah as saying that the reform of Christianity 500 years ago was greatly facilitated by the fact that on encountering morally ambiguous, contradictory or problematic passages, ordinary Christians who started reading the Bible for themselves decided on "which passages to read into and which to read past." Simply stated, the reformists chose to "cherry-pick" from among the passages of the Bible, embracing what was appealing, skirting around what seemed appalling.

But how do you "read past" any verse of the Quran if as a believing Muslim for you it is an absolute article of faith that the Quran is the Word of Allah revealed to Prophet Mohammed through the Archangel Gabriel? For a believing Muslim who agrees that any meaningful reform in Islam today must necessarily address the issue of equality between the sexes, there is no way to skirt around 4:34. You simply have to engage with it. But then, how do you reconcile your faith in an Allah who endorses male superiority and recommends wife-beating with your fidelity to the principle of gender justice?

To get around this thorny issue some current-day Muslims resort to a linguistic device, claiming that the Arabic word "darab" in the verse has meanings other than "beating". The fact, however, is that the overwhelming majority of exegetes, the liberal ones included, accept the translation of "darab"(d-r-b) as physical chastisement. The only dispute is over issues such as at when it's OK to beat and the permissible intensity of the beating (according to some a feather or a flower are the only permissible weapons). The late Moroccan Islamic scholar, Fatima Mernissi, notes that the immediate context of the revelation of verse 4:34 was a woman's complaint to the Prophet that her husband had slapped her. The revelation then had necessarily to address the issue of wife-beating.

While this issue remains a knotty one, in recent years several women (and men) scholars of Islam — Mernissi, Amina Wadud, Riffat Hassan, Asma Barlas among others — have credibly argued that the Quran is a gender-sensitive document. For them, it is the exegetes with patriarchal mindsets who are responsible for having read patriarchy into the Quran. For example, in her book, Believing women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Quran, Asma Barlas argues: "The Quran recognises men as the locus of power and authority in actually existing patriarchies. However, recognising the existence of patriarchy, or addressing one, is not the same as advocating it".

Interestingly, while many Muslim women scholars and activists see Allah as being entirely on their side in their "gender jihad" against the patriarchs of Islam (ulama), South Africa's Farid Esack, a male educated in a Pakistani madrasa, a believing, practising Muslim, an Imam to boot, has an interesting point to make. Esack agrees that the Quran does contain "sufficient seeds for those committed to human rights and gender justice to live in fidelity to its underlying ethos". But he argues that the liberal Muslim claim that "the Quran is a Magna Carta of gender justice does not withstand the scrutiny of critical scholarship". In a paper titled, "What Do Men Owe to Women? Islam & Gender Justice: Beyond Simplistic Apologia", Esack labels several renowned "liberal" Islamic scholars as "Islam's apologists".

To drive his point home, Esack quotes the late Anglican Bishop Kenneth Cragg who observed: "The eternal cannot enter time without a time when it enters. Revelation to history cannot occur outside it. A prophet cannot arise except in a generation and a native land, directives from heaven cannot impinge upon an earthly vacuum." In other words, constrained by the time and place of revelation — seventh century Arabia — the Quran could not possibly be a Magna Carta of gender justice, speaking the language of the 21st century. (Even today, 15 centuries later, gender injustice plagues the world cutting across communities, countries and cultures).

Mernissi says the same thing differently: "If men had need of God, God also had need of men". In her book, Women and Islam, she points out that the gender question almost precipitated a civil war within the very first generation of Muslims. "Faced with the difficult choice — equality between the sexes or the survival of Islam — the genius of Mohammed and the greatness of his God shows in the fact that at least at the beginning of the seventh century the question was posed and the community was pushed to reflect on it". She blames the later exegetes for not pushing the envelope.

Esack who has issues not only with verse 4:34 but with others too pertaining to gender has no hesitation saying: "If a choice has to be made between violence towards the text and textual legitimisation of violence against real people (women) then I would be comfortable to plead guilty to charges of violence against the text". Esack has no difficulty in quarrelling with the Book for "my theology is about a God that is essentially just and compassionate".

Notwithstanding the differences between the different strands within Islam — traditional, liberal, progressive, extremist — one thing has remained a constant among most believing Muslims: The belief that the Quran is the Word of Allah.

But now enters a British Muslim, Hassan Radwan. In an article recently published by the online portal New Age Islam, he makes an altogether radical prescription for salvaging Islam from "the hardline literalists undermining the soul of a loving, universal creed". According to him, "Liberal and progressive interpretations depend mostly on nuanced readings of the Quran and Sunna, or forcing new meanings out of them. But by playing the extremists' game of interpreting the texts, we allow them a semblance of legitimacy. We also give them the opportunity to come back with theological workarounds".

So, what is to be done? Radwan's answer: "We Muslims need to take the bold step of challenging the very idea that the Quran and Sunna are infallible." But how can the Quran, the word of God, be fallible? Simple. "The Quran is not the speech of God", he maintains, quoting several modern-day Muslim scholars as also quite a few from the early period of Islam in support.

According to Radwan, once Muslims accept that the Quran is not the Word of God, they can "unashamedly cherry-pick" from among the Quranic verses, accepting the good ones and rejecting the bad. Like the Christian reformists did 500 years ago?

The writer is general secretary, Muslims for Secular Democracy, and co-editor, 'Communalism Combat'

http://indianexpress.com/article/opinion/columns/islams-reform-way-to-go-triple-talaq-quran-4756857/

***

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या **0636000102165381** जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशि:

पांच वर्ष : 600 रुपए

एक वर्ष : 150 रुपए

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 20 ● Issue 17 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● Total Pages 8 ● 16 to 31 July, 2017

Social Message of Presidential Election

Dr. Udit Raj

It was well anticipated that Shri Ramnath Kovind would secure the victory with comfortable majority. Some MPs and MLAs outside the NDA also voted for him. Shri Ramnath Kovind received more votes than expected. His appointment at the highest office in the country is seen as a strength of the Indian democracy. This election was not a routine because for the second time a person from marginalized section was fielded for this highest post and it was but natural that the debate around it could happen. It was a big surprise that his name was announced all of a sudden which was not in domain of discussion. Everyone including media were taken by surprise. This forced the UPA to give their candidate from the same section. Due to the decision of congress this presidential election became a question of Dalit v/s Dalit. In some section this could have become heart burn issue as why a candidate for the President of India is being termed as Dalit ? To them, the candidate would have been known or publicized as Indian.

Even though the president has limited executive power, but still it is the highest position in the country. At the same time, he is the guardian of constitution and the chief of army. Ever since the concept welfare state has emerged, more or less all over the world it is being attempted to have inclusive governance. Giving a chance to a person from down trodden section to the highest position is an attempt to have inclusive governance. These actions are necessary to convey message of equality and justice to the left over class in the society. Indian social system is very different from others in the world. Other countries do not have caste and spiritual based discriminatory system. To some it will appear an appeasement but they should know under what circumstances these marginalized and so called lower caste dwell in the society. Those who are on upper strata in the society, they can't imagine the sufferings of scheduled caste, scheduled tribe and backwards. If such people who think that caste is a thing of past, to know this reality they should live the life of these untouchables for a day, it is guaranteed that they will change their notion. Had they worked in tanneries, lifted and cleaned the excreta of other human beings they would have realized that what is the suffering of people from where Shri Ramnath Kovind comes from. There is unending miseries of these people and fielding him for this post is a minor attempt of reparation.

In June 1893, when Mahatama Gandhi was travelling in South Africa on a first class train ticket then he was asked to move to the third class, because he was not white. Since he had a first class ticket so he protested and then he was forcefully dropped on the railway station. He could not bear this humiliation and kept thinking about it the whole night at the station and finally in the end he decided to fight against this injustice. What happened with Gandhi Ji is very small as compared to what has continued to happen with uncountable Dalits and the disadvantaged for thousands of years. If this is viewed in this context, then the election of Shri Ramnath Kovind as the second dalit president is to support and motivate the suppressed sections of society. It is the duty of every citizen to support this cause not only in the interest of these marginalized communities but for the progress of nation. Any society which is so inequal like ours it would be day dreaming to catch up developed countries of the world. Brethren and sister who feel that why the merit is being compromised, they should introspect in the light of above facts and what happened to Gandhi Ji. Those who are reeling under such circumstance for thousand years, Gandhi Ji could not bear for a day and vowed to over throw the British regime.

In India, the society is fragmented into thousand groups – castes. It is in the interest of the nation that all those be it Dalit, OBC, minority or women are given fair representation in all walks of life. By ensuring participation of each section only, not only it will help in growth of the country but also create conducive environment to its citizen to have choice, freedom and happiness. Electing Shri Ramnath Kovind as the president is a step so that in times to come no one feels that he is backward or neglected. If this sense of feeling prevails in our society that would address major issues which impede to create healthy society. Waiting for that moment when things will be decided on the basis of merit and it is possible when the society abridges the gap between caste and gender and so on so forth.

Recently there was a seminar on national security in Delhi. While speaking I was reminded of Israel at that time our Prime Minister Narendra Modi was also in Israel. I had to say if our society was also united like Israel then a unsuccessful country like Pakistan would not have the audacity to export terrorism. Election of Shri Ramnath Kovind as the second dalit president of India is a step towards uniting the society and also moving ahead towards progress. As long as division on the basis of caste persist till that day phenomenon like of presidential candidate will be continued. His election has not only political ramification but in all walks of life.

-The writer is a member of Lok Sabha.

***

Appeal to the Readers

You will be happy to know that the **Voice of Buddha** will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through Bank draft in favour of **'Justice Publications'** at T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in 'Justice Publications' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi, under intimation to us by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that you don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution:
Five years : Rs. 600/-
One year : Rs. 150/-

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com Computer typesetting by C. L. Maurya